F.No. 1(11)/2018-Coord.
Government of India
Ministry of Finance
Department of Public Enterprises
Block No.14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi – 110003
Dated the 22 August, 2022

Subject: Monthly Summary of Principal activities of Department of Public Enterprises for circulation to the Council of Ministers-reg.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat's O.M. No. 1/26/1/2018-Cab. dated 19th August, 2019 on the subject mentioned above and to enclose monthly summary pertaining to the Department of Public Enterprises for the month of **July, 2022**.

(Naresh Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph: 24366820
Email: - us-admn-dpe@nic.in

Encl: As above

To,

All Members of the Council of Ministers.

Copy to: -

1. PS to Hon.MoS(Finance).
2. All Secretaries to the Govt. of India's Ministries/ Departments
3. Shri Puru Gupta, Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
4. PPS to Secretary (PE)/PPS to SS (RKC)/PS to JS (SKJ)/ PA to Principal Advisor (PK)/PSO to Advisor (AB)/ PS to DDG (AKN)
5. Sr. Technical Director (NIC) for uploading on the DPE website.

Ministry of Finance
Department of Public Enterprises
Monthly Summary for the Cabinet for the month of July, 2022

An update on the principal activities and key initiatives under taken by the Department of Public Enterprises (DPE) during the month of **July, 2022** is indicated below: -

1. CAPEX targets:

The information relating to capital expenditure by select CPSEs and other Government organizations for the month of July, 2022 was submitted to PMO on 5th August, 2022. Against Budget Estimates for annual CAPEX of Rs. 6.62 lakh crores, the achievement was Rs. 1.84 lakh crores i.e. about 28%, as on 31.07.2022.

2. Closure of CPSEs:

A draft CCEA Note for "in-principle" approval for closure of 2 units of Hindustan Insecticides Ltd. at Udyogamandal, Kerala and Bathinda, Punjab and strategic disinvestment of Rasayani Unit, Maharashtra was circulated for inter-ministerial consultation on 20.07.2022.

3. Governance of CPSEs:

i) DPE organized the first ever "Induction & Capacity Building Workshop" of Independent Directors (ID) in collaboration with Capacity Building Commission (CBC) & Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) as knowledge partners. Three programs of two days duration were conducted between 11th – 17th July, 2022 in which 326 Non official Directors (NoDs) of various CPSEs participated.

ii) A National Workshop on Environmental, Social, and Governance (ESG) Reporting by CPSEs was organized on 29.07.2022 in New Delhi in association with NPC. Approx. 50 listed CPSEs participated in the workshop.

iii) The proposal of Department of Personnel Training (DoPT) for Initial Categorization of Mission Karmyogi Bharat as Schedule "A" CPSE was considered in consultation with Public Enterprises Selection Board and concurred with.

iv) Instructions to CPSEs on mechanism of seeking vigilance clearance in respect of private person appointed on the board of

CPSEs were issued.

v) The revival of the post of Director (Operation) in the Cement Corporation of India Limited was approved.

vi) Proposal of Brahmaputra Crackers & Polymers Limited for creation of 3 posts at E-8 level was approved.

vii) 92 operating CPSEs which have not onboarded TReDS platform were directed to do so.

viii) Training programmes/ workshops to be conducted under RDC scheme of the Department for the Executives of CPSEs for the year 2022-23 were finalized.

ix) DA rates due from 01.07.2022 for Board level and below Board level Executives including non-unionized Supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) following IDA pattern pay scales 2017, 2007,1997, 1987 and 1992 were notified vide DPE OMs dated 06.07.2022 & 13.07.2022 respectively.

4. Inter-Ministerial Meetings and Cabinet Notes/ CCEA Notes:

Comments on the following notes circulated for inter-ministerial consultations were furnished: -

a) Draft Model Bye-laws for Primary Agricultural Credit Society (PACS) circulated by the Ministry of Cooperation.

b) Draft Note for the Cabinet on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022 circulated by the Ministry of Cooperation.

c) Draft Concept Note circulated by Ministry of New & Renewable Energy on CPSU/ CPSE Programme for implementation of Renewable Energy Projects.

d) Draft Cabinet Note circulated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade for introduction of The Amendment Bill, 2022 for enhancing Ease of Doing Business and Ease of Living.

e) Draft Cabinet Note circulated by the Ministry of Electronics & Information Technology on Approach and Implementation Strategy for 2nd phase of Digital India Programme.

5. Special Events: Azadi Ka Amrit Mahotsav:

All the CPSEs under different Ministries/Departments were requested to draw action plan to promote 'Har Ghar Tiranga' programme as per instructions of Government of India.

*****

वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2022 माह हेतु मासिक सारांश

जुलाई, 2022 माह के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां और महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में एक अद्यतन रिपोर्ट (अपडेट) निम्नवत है:-

1. **कैपेक्स लक्ष्य:**

चुनिंदा सीपीएसईज़ और अन्य सरकारी संगठनों के जुलाई, 2022 माह के लिए पूंजीगत व्यय से संबंधित जानकारी दिनांक 05 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 6.62 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक कैपेक्स के बजट अनुमान की तुलना में दिनांक 31.07.2022 की स्थिति के अनुसार, उपलब्धि 1.84 लाख करोड़ रुपये अर्थात लगभग 28% थी।

2. **सीपीएसई को बंद करना:**

उद्योगमंडल, केरल और भटिंडा, पंजाब में हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइट्स लिमिटेड की 2 इकाइयों को बंद करने और रसायानी इकाई, महाराष्ट्र के रणनीतिक विनिवेश के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन हेतु सीसीईए नोट का मसौदा दिनांक 20.07.2022 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया था।

3. **सीपीएसईज़ का गवर्नेंस:**

i) डीपीई ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) के सहयोग से ज्ञान भागीदारों के रूप में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की प्रथम "प्रेरण और क्षमता निर्माण कार्यशाला" का आयोजन किया। 11 से 17 जुलाई, 2022 के बीच दो दिनों की अवधि के तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न सीपीएसई के 326 गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) ने भाग लिया।

ii) एनपीसी के सहयोग से दिनांक 29.07.2022 को नई दिल्ली में सीपीएसईज़ द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस रिपोर्टिंग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में लगभग 50 सूचीबद्ध सीपीएसईज़ ने भाग लिया।

iii) अनुसूची ''क'' सीपीएसई के रूप में मिशन कर्मयोगी भारत के आरंभिक वर्गीकरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रस्ताव पर लोक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से विचार किया गया था और इस पर सहमति व्यक्त की गई थी।

iv) सीपीएसईज़ के बोर्ड में निजी व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में सतर्कता संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के तंत्र पर सीपीएसईज़ को निर्देश जारी किए गए थे।

v) सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के पद की बहाली को मंजूरी दी गई।

vi) ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड के ई-8 स्तर पर 3 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

vii) 92 प्रचालनरत सीपीएसईज़ जिन्होंने टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया गया था।

viii) वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसईज़ के कार्यपालकों के लिए विभाग की आरडीसी योजना के तहत आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं को अंतिम रूप दिया गया।

ix) आईडीए पैटर्न वेतनमान 2017, 2007, 1997, 1987 और 1992 के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के लिए दिनांक 01.07.2022 से देय डीए दरों को डीपीई के कार्यालय ज्ञापन क्रमशः दिनांक 06.07.2022 और 13.07.2022 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और मंत्रिमंडल नोट्स / सीसीईए नोट्स:

अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के लिए परिचालित निम्नलिखित नोट्स पर टिप्पणियां भेजी गई:-

क) सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) के लिए मॉडल उप-नियम का मसौदा परिचालित किया गया।

ख) सहकारिता मंत्रालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक, 2022 पर मंत्रिमंडल के लिए मसौदा नोट परिचालित किया गया।

ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीपीएसयू/सीपीएसई कार्यक्रम पर अवधारणा नोट का मसौदा परिचालित किया गया।

घ) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा व्यापार करने में आसानी और जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक, 2022 को पेश करने के लिए मंत्रिमंडल नोट का मसौदा परिचालित किया गया।

ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए दृष्टिकोण और कार्यान्वयन रणनीति पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा परिचालित मंत्रिमंडल नोट का मसौदा परिचालित किया गया।

5. विशेष कार्यक्रम: आजादी का अमृत महोत्सव:

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी सीपीएसईज़ से अनुरोध किया गया था कि वे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

*****